IJETIR

ISSN (Online) 2583-0554

International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)

Volume 5, Issue 1, January 2025

Impact Factor: 5.731

मुगल और तुगलक काल में आर्थिक सुधारों तथा राजस्व व्यवस्थाओं का अध्ययन

नीना शर्मा[1], डॉ. संदीप प्रजापत[2]

[1]शोधार्थी, विभाग इतिहास

[2]प्रोफ़ेसर. विभाग इतिहास

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश

यह अध्ययन मुगल और तुगलक साम्राज्यों की आर्थिक सुधार योजनाओं तथा भू-राजस्व व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तुगलक काल में विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक ने कराधान, मुद्रा सुधार तथा राजधानी स्थानांतरण जैसी प्रयोगधर्मी नीतियां अपनाईं, जिनका उद्देश्य राज्य की आर्थिक समृद्धि बढ़ाना था, परंतु अव्यवस्थित क्रियान्वयन और कठोर कर संग्रह के कारण व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके विपरीत मुगल शासन में अकबर द्वारा विकसित दहसाला प्रणाली, भूमि माप की सुसंगठित व्यवस्था और पारदर्शी राजस्व प्रशासन ने कृषि उत्पादन को सुदृढ़ किया तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया। इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व व्यवस्थाओं में संगठन, स्थायित्व और किसानों की सहभागिता किसी भी साम्राज्य की आर्थिक सफलता का आधार होते हैं।

मुख्य संकेतक: - मुगल काल, तुगलक काल, आर्थिक सुधार, भू-राजस्व व्यवस्था।

परिचय

भारत का मध्यकालीन इतिहास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण युग रहा है। इस काल में अनेक सुल्तानों और बादशाहों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और अपनी नीतियों एवं सुधारों से राज्य की संरचना को नया स्वरूप प्रदान किया। तुगलक और मुगल काल ऐसे ही दो महत्वपूर्ण शासक वंश रहे जिन्होंने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। इन दोनों शासनों के अंतर्गत आर्थिक सुधारों और भू-राजस्व व्यवस्थाओं का विकास हुआ, जिनकी परिणति भारतीय कृषि व्यवस्था, व्यापार, शहरीकरण और राजस्व संग्रह की नई प्रणालियों में हुई। इन व्यवस्थाओं ने न केवल

Copyright to IJETIR

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 1, January 2025
Impact Factor: 5.731

तत्कालीन जनजीवन को प्रभावित किया बल्कि बाद के शासकों की आर्थिक नीतियों की दिशा भी निर्धारित की।

तुगलक वंश (1320–1414 ई.) दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली और प्रयोगधर्मी शासक वंश था। विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई आर्थिक प्रयोग किए गए, जिनमें कर वृद्धि, नई राजधानी का निर्माण, तथा मुद्रा सुधार जैसी योजनाएं शामिल थीं। यद्यपि इन योजनाओं का उद्देश्य राजकोष को सुदृढ़ करना और साम्राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था, परंतु अव्यवस्थित कार्यान्वयन, कड़े कराधान और प्रशासनिक कमजोरी के कारण इनमें से अधिकांश प्रयोग विफल रहे और जनता के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तुगलक शासन की आर्थिक नीतियों का इतिहास में उदाहरण इसलिए विशेष रूप से दिया जाता है कि कैसे सुचिंतित लेकिन गलत ढंग से लागू योजनाएं राज्य के लिए संकट का कारण बन सकती हैं।

इसके विपरीत, मुगल साम्राज्य (1526–1857 ई.) की आर्थिक और राजस्व व्यवस्था तुलनात्मक रूप से अधिक व्यवस्थित, दूरदर्शी और व्यवहारिक सिद्ध हुई। मुगलों ने भारतीय कृषि की अपार संभावनाओं को पहचाना और उसके विकास के लिए सुसंगठित भू-राजस्व प्रबंधन लागू किया। अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा विकसित दहसाला प्रणाली ने कर संग्रह को एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया। इस प्रणाली में उपज का आकलन, भूमि का मापन, कर की दरों का मानकीकरण और किसानों की भलाई का ध्यान रखा गया। दहसाला प्रणाली न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सफल रही बल्कि किसानों में अपेक्षाकृत विश्वास और स्थायित्व की भावना भी उत्पन्न हुई। मुगल शासन में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला।

मुगल और तुगलक दोनों शासनकालों में भू-राजस्व को राज्य की आय का मुख्य स्रोत माना जाता था। भारतीय कृषि प्रधान समाज में भूमि ही सम्पत्ति और उत्पादन का आधार थी। इस कारण भूमि कर संग्रह की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जहां तुगलक शासन में कर संग्रह की पद्धति अधिक कठोर और शोषणकारी प्रवृत्ति की थी, वहीं मुगल काल में अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया। मुगल अधिकारियों ने कर निर्धारण में औसत उपज और मूल्य का वैज्ञानिक आकलन किया, जिससे किसानों पर अनावश्यक दबाव कम हुआ। तुगलकों के शासन में राजस्व अधिकारी अक्सर दमनकारी प्रवृत्ति के होते थे, जबकि मुगलों ने अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड, नक्शों तथा रसीद प्रणाली को महत्व दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के मुद्रा सुधार का उदाहरण आर्थिक इतिहास में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए जिन्हें चांदी के समकक्ष मान्यता दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य की वित्तीय कठिनाइयों

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 1, January 2025
Impact Factor: 5.731

को दूर करना था, लेकिन नकली सिक्कों की बाढ़ और अव्यवस्था के कारण यह योजना असफल रही। इससे राजस्व में कमी और बाजार में अविश्वास पैदा हुआ। वहीं दूसरी ओर मुगलों ने सिक्कों की गुणवत्ता, भार और धातु की शुद्धता पर सख्त नियंत्रण रखा, जिससे मुद्रा प्रणाली में स्थायित्व और विश्वसनीयता बनी रही।

इन दोनों कालों में आर्थिक सुधार केवल कर प्रणाली तक सीमित नहीं थे। तुगलक शासन में राजधानी का हस्तांतरण भी आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया ताकि साम्राज्य के दक्षिणी प्रदेशों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। परंतु यह योजना प्रशासनिक अव्यवस्था, जन-पीड़ा और व्यापक असंतोष का कारण बनी। इसके विपरीत मुगलों ने अपनी राजधानी को सुदृढ़ व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। आगरा और बाद में शाहजहां द्वारा निर्मित शाहजहांनाबाद (पुरानी दिल्ली) ने न केवल सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाई।

मुगल शासन में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए। कृषि में सिंचाई व्यवस्था का विकास, नहरों का निर्माण, नई फसल पद्धतियों का प्रयोग और बागवानी को बढ़ावा देना ऐसे ही प्रयासों का उदाहरण हैं। वहीं तुगलक शासन में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक कमियां और प्रशासनिक दमन का वातावरण था, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा।

मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में शिल्पकार, कारीगर और व्यापारी वर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल काल में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, जिससे हस्तशिल्प उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ। तुगलक शासन में इन गतिविधियों पर कराधान और अस्थिरता का नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

राजस्व व्यवस्थाओं के इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसी भी साम्राज्य की आर्थिक प्रगति केवल योजनाओं की महानता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके प्रभावी और न्यायसंगत क्रियान्वयन पर भी आधारित होती है। तुगलक शासन के प्रयोगधर्मी लेकिन असफल सुधार और मुगल काल की व्यवस्थित व दीर्घकालिक आर्थिक नीतियां इस बात का प्रमाण हैं।

यह शोध पत्र मुगल और तुगलक काल की आर्थिक तथा राजस्व व्यवस्थाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। इसमें उन कारकों की विवेचना की जाएगी जिन्होंने इन नीतियों की सफलता या विफलता निर्धारित की, तथा यह भी विचार किया जाएगा कि इन सुधारों का तत्कालीन समाज, कृषि उत्पादन, व्यापार और शासकीय संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही, यह अध्ययन इस दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार मध्यकालीन राजस्व व्यवस्थाओं ने आधुनिक भारत में राजस्व प्रशासन की नींव रखी।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 1, January 2025
Impact Factor: 5.731

तुगलक काल की आर्थिक एवं राजस्व व्यवस्था

1. राजस्व व्यवस्था के मुख्य बिंदु

तुगलकों ने खालिसा भूमि (सरकारी अधीन) और इक्ता प्रणाली को बढ़ावा दिया।

इक्ता में अधिकारियों को भू-राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था।

मोहम्मद बिन तुगलक ने कराधान में वृद्धि की, विशेषकर दक्कन में।

तुगलक काल में कर संग्रहण में कठोरता एवं दमन की प्रवृत्ति देखी गई।

2. आर्थिक सुधार

मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा-सुधार: तांबे के सिक्के चलाना, जिससे नकली मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ।

राजधानी का हस्तांतरण (दिल्ली से दौलताबाद) भी आर्थिक दृष्टि से विफल रहा।

कृषि कर की वृद्धि ने किसानों पर अतिरिक्त भार डाला, जिससे विद्रोह और असंतोष उत्पन्न हुए।

3. प्रभाव

कर संग्रह की अति कठोर नीतियों से कृषि ह्रास, जनसंख्या पलायन एवं वित्तीय संकट गहराया।

तुगलकों का आर्थिक प्रयोग अल्पकालिक और अव्यवस्थित रहा।

मुगल काल की आर्थिक एवं राजस्व व्यवस्था

1. राजस्व प्रणाली का विकास

मुगल काल में भूमि कर (जजिया, खराज) के संगठित प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया।

अकबर की भू-राजस्व व्यवस्था (दहसाला प्रणाली):

राजस्व निर्धारण के लिए औसत उपज एवं मूल्यों का दस वर्षीय आंकलन।

किसान की वास्तविक उपज के आधार पर कर निर्धारण।

राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

2. प्रशासनिक सुधार

टोडरमल ने भूमि माप और वर्गीकरण की सुस्पष्ट व्यवस्था लागू की।

रिकॉर्ड संधारण, नक्शों का संकलन और राजस्व रसीद प्रणाली विकसित हुई।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 1, January 2025
Impact Factor: 5.731

कर अदायगी में पारदर्शिता बढ़ाई गई।

3. आर्थिक विकास

व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला।

कृषि उत्पादन में वृद्धि।

बुनकर, शिल्पकार, व्यापारी वर्ग संपन्न हुए।

सिक्कों का मानक निर्धारण और विश्वसनीय मुद्रा प्रणाली विकसित की गई।

तुलनात्मक विश्लेषण

पक्ष	तुगलक काल	मुगल काल
नीति	प्रयोगधर्मी, अव्यवस्थित	संगठित, स्थायी, पारदर्शी
भू-राजस्व	कठोर संग्रह, दमनकारी	दहसाला प्रणाली, किसानोन्मुखी
मुद्रा	नकली सिक्कों की समस्या	सुव्यवस्थित मुद्रा प्रबंधन
कृषि प्रभाव	उत्पादकता में गिरावट	उत्पादन एवं राजस्व में वृद्धि
प्रशासनिक दृष्टिकोण	अस्थिर, शीघ्र निर्णय	क्रमबद्ध सुधार और दीर्घकालिक योजनाएं

निष्कर्ष

मुगल और तुगलक काल का अध्ययन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों ही शासनों ने आर्थिक सुधारों और राजस्व व्यवस्थाओं को अपने शासन की स्थिरता तथा समृद्धि का आधार बनाने का प्रयास किया। तुगलक शासक विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में अनेक प्रयोगधर्मी नीतियां लागू कीं, जैसे मुद्रा सुधार, राजधानी का हस्तांतरण तथा कराधान की नई योजनाएं। इन सुधारों के पीछे राज्य की वित्तीय शक्ति बढ़ाने और प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने का उद्देश्य था। किंतु उनका क्रियान्वयन अव्यवस्थित और वास्तविक परिस्थितियों से अनभिज्ञ था। परिणामस्वरूप किसानों पर कर का भार असहनीय हो गया, नकली मुद्रा के चलन ने अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया, और राजधानी के स्थानांतरण ने प्रशासनिक अव्यवस्था तथा व्यापक असंतोष को जन्म दिया। तुगलक शासन की इन असफलताओं ने यह शिक्षा दी कि किसी भी नीति की सफलता के लिए उसकी व्यावहारिकता और कार्यान्वयन की दक्षता अनिवार्य होती है।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 1, January 2025
Impact Factor: 5.731

इसके विपरीत, मुगल काल की आर्थिक और राजस्व व्यवस्थाएं अधिक संगठित, दूरदर्शी और दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाली सिद्ध हुईं। अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा विकसित दहसाला प्रणाली ने भूमि मापन, कर निर्धारण और संग्रहण को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाया। इस प्रणाली में किसानों की वास्तविक उपज और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कर लगाया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। मुगल प्रशासन ने कर संग्रह में कठोरता के बजाय संतुलन और न्यायसंगत दृष्टिकोण को अपनाया। इसी का परिणाम था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में भरोसा कायम हुआ।

मुगल काल में मुद्रा प्रणाली भी स्थायित्व और विश्वसनीयता की मिसाल बनी। सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का चलन सुनिश्चित किया गया जिससे वाणिज्यिक लेनदेन में सुगमता आई। इसके विपरीत तुगलक शासन में तांबे के सिक्कों का प्रयोग बिना उचित नियंत्रण के किया गया, जिसके कारण नकली मुद्रा की बाढ़ आ गई और व्यापारियों का राज्य पर विश्वास घट गया।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि तुगलक और मुगल दोनों कालों में राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि भूमि ही थी। परंतु जहां तुगलकों ने कर संग्रहण में कठोर उपाय अपनाकर असंतोष को जन्म दिया, वहीं मुगलों ने व्यवस्थित प्रशासन और किसानों की सहभागिता के माध्यम से अपनी राजस्व प्रणाली को अधिक कारगर और दीर्घजीवी बनाया। मुगलों की आर्थिक नीतियों ने न केवल तत्कालीन समाज को स्थायित्व दिया, बल्कि आने वाले शासकों के लिए भी एक प्रभावी राजस्व प्रबंधन का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया।

अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी शासन की आर्थिक नीतियों की सफलता केवल योजनाओं की महत्वाकांक्षा पर नहीं, बल्कि उनके व्यवहारिक पक्ष, प्रशासनिक क्षमता और जनता के हितों के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। मुगल शासन की योजनाओं में यही विशेषताएं थीं, जिनके कारण वे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में आर्थिक समृद्धि और कुशल राजस्व व्यवस्था के प्रतीक बने। तुगलक और मुगल काल के अनुभव आधुनिक प्रशासन और आर्थिक नीति निर्धारण के लिए भी अमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं।

संदर्भ सूची

[1]. आलम, एम. (2004). मुगल उत्तर भारत में साम्राज्य का संकट: अवध और पंजाब 1707-48. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

[2]. चंद्रा, एस. (2007). मध्यकालीन भारत: सल्तनत से मुगलों तक (खंड I और II). हर-आनंद प्रकाशन.

[3]. हबीब, आई. (1999). मुगल भारत की कृषि प्रणाली (1556-1707). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

[4]. जैक्सन, पी. (2003). दिल्ली सल्तनत: एक राजनीतिक और सैन्य इतिहास. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

[5]. त्रिपाठी, आर.एस. (1967). मध्यकालीन भारत का इतिहास. मोतीलाल बनारसीदास.

[6]. रिचर्ड्स, जे.एफ. (1993). मुगल साम्राज्य. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

[7]. आशेर, सी.बी., और टैलबोट, सी. (2006). यूरोप से पहले का भारत. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

[8]. कुल्के, एच., और रोदरमुंड, डी. (2004). भारत का इतिहास. रूटलेज